International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 2, March-April, 2026

प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना का सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभावः नीमकाथाना ब्लॉक – जिला सीकर, राजस्थान का एक भौगोलिक अध्ययन

कैलाश चन्द जाट[1], डॉ. हेमेंद्र सिंह शक्तावत[2]

[1]शोधार्थी, भूगोल विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविधालय उदयपुर, राजस्थान
[2]शोध निर्देशक, भूगोल विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविधालय उदयपुर, राज.

शोध सारांश

किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति एवं उन्नति वहां पाये जाने वाले संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर निर्भर करती है और इस हेतु विकसित परिवहन जाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत देश की कुल आबादी का 68.84 प्रतिशत (83.3 करोड़) भाग गांवो में निवास करती है। (जनगणना 2011) अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान देश में ग्रामीण सड़को का विकास महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर ग्रामिण क्षेत्रों के विकास हेतु अनेक योजनाओं का विकास व निर्माण किया गया है। इन्हीं में से एक 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (पी. एम. जी. एस. वाई.) है। जो 25 दिसम्बर, 2000 को असम्बद्ध अधिवासों को अन्य गांवो, ठाणियों, कस्बों नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने हेतु प्रारम्भ की गई। प्रस्तुत अध्ययन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े लोगों और अधिवासों का सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं। क्षेत्र अवलोकन एवं आँकड़ो के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवहन सुविधाओं में विस्तार सें गति आयी एवं रोजगार के नये अवसरों, आय अर्जन स्त्रोतों में बदलाव के साथ वृद्धि हुई, जिसे गरीबी निवारण के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार के रुप में सामाजिक–आर्थिक विकास हो पाया है।

मुख्य शब्दः पी. एम. जी. एस. वाई.सामाजिक, आर्थिक, विकास, जीवनस्तर, वार्षिक आय, ग्रामीण जुड़ाव, कृर्षि उत्पादकता, गरीबी निवारण, परिवहन लागत।

प्रस्तावना

''परिवहन एक सभ्यता है जो लोगों के विकास व प्रगती के लिए अतिआवश्यक है।''

–डेविस, डी. एच.

भारत देश के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब छह लाख पचास हजार गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए चुनौती के साथ–साथ अवसर भी है। इन सुविधाओं में बिजली, पानी, आवास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मुलभूत आवश्यकताएँ है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्गो से जोड़ने हेतु तीव्र, समग्र व सतत् विकास उपलब्ध कराने व ग्रामीण भारत का सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण करने के उद्देश्य स्वरुप '' प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना '' 25 दिसम्बर 2000 को प्रारम्भ की। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों वाली सड़क उपलब्ध कराना। इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों या सामान्य आबादी क्षेत्रों में 500 व इससे अधिक की आबादी के सभी गांवों को तथा पहाड़ी राज्यों, जनजातिय व मरूस्थलीय क्षेत्रों में 250 व इससे अधिक आबादी के सभी गांवों को एवं इन्हीं जनसंख्या समूहों में ढाणी/मजरों को सभी मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है। इस योजना को राज्य में लागू करने हेतु '' राजस्थान ग्रामिण सड़क विकास एजेंन्सी'' नोडल एजेन्सी के रुप में कार्य करती है।

इस योजना के अंतर्गत देश में मार्च 2025 तक 1,71,525 बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है जो कुल बसावटों का लगभग 85 प्रतिशत है, और वित बर्ष 2024 से 2028 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–**IV** को क्रियानवित किया जायेगा जिसमे 25000 बस्तियों को नए सड़क मार्ग से जोडने के लिए 62500 किलोमीटर नई सड़को का निर्माण किया जायेगा।

ग्रामिण आर्थिक विकास सड़को के जुड़ाव से विभिन्न प्रकार से प्रभावित होता है जैसे – गरीबी निवारण उत्पादकता में वृद्धि, कृषि भूमि उपयोग व फसल प्रारुप में परिवर्तन, वित्तीय सेवाओं व रोजगार अवसरो में वृद्धि, गत्यात्मकता, कृषि विकास में उन्नत बीज व उर्वरकों की उपलब्धता, कृषि में आधुनिक मशीनीकरण की सुलभता, कृषि उपजो की बाजारमण्डी तक सुगम पहुँच, बाजारों का विस्तार होना, धार्मिक पर्यटन केन्द्रों का विकास एवं ग्रामीण उघोगों का विकास आदि। ग्रामीण सड़क विकास से यात्री व माल परिवहन सुविधाओं का विस्तार व परिवहन साधनों के उपयोग में वृद्धि, हुई हैं। जिससे परिवहन लागत में कमी तथा समय की बचत हुई हैं। इसके साथ–साथ सड़क मार्गो के विकास से सामाजिक विकास पर भी प्रभावित हुआ हैं जिसमें शैक्षिक संस्थानों तक पहुँज कें सुगमता, स्वास्थ्य सेवाअसें की उपलब्ध्ता, जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक रीति–रिवाजों एवं रिश्तों में बदलाव आदि प्रमुख है।

अध्ययन क्षेत्र

नीमकाथाना तहसील का अक्षांशीय विस्तार 27°56' से 27°88 ' उत्तरी अक्षांश व देशांतरीय विस्तार 75°58' से 75°96 ' पूर्वी देंशांतर है। नीमकाथाना तहसील की उत्तरी सीमा हरीयाणा राज्य के रेवाड़ी जिला से, पूर्वी सीमा कोटपूतली,दक्षिणी सीमा सीकर जिले श्रीमाधोपुर तहसील व पश्चिमी सीमा झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील से लगती है। नीमकाथाना तहसील मुख्यालय सीकर जिला मुख्यालय से 83 किमी उत्तर–पूर्व में स्थित हैं।

इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1203 वर्ग किमी एवं कुल जनसंख्या 399911(2011) हैं। तहसील में 192 कुल आबाद गाँव हैं। तहसील मुख्यालय की समुन्द्र तल से औसत ऊंचाई 446 मीटर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तहसील में जन घनत्व 339 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हैं। नीमकाथाना तहसील मुख्यालय से दिल्ली–मुम्बई रेलवे कोरीडोर गुजरता हैं। और नीमकाथाना तहसील मुख्यालय से राज्य राज मार्ग गुजरता हैं।

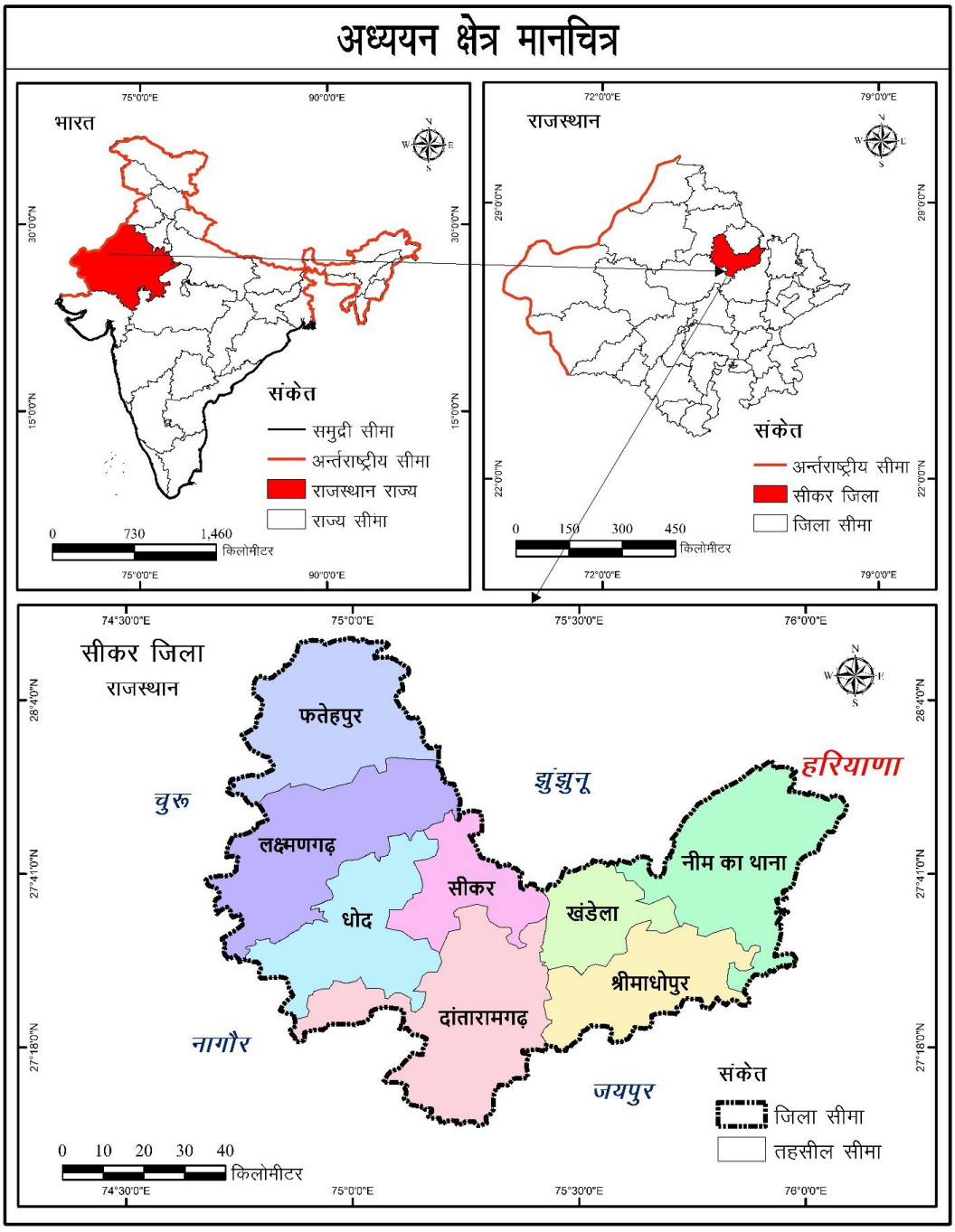

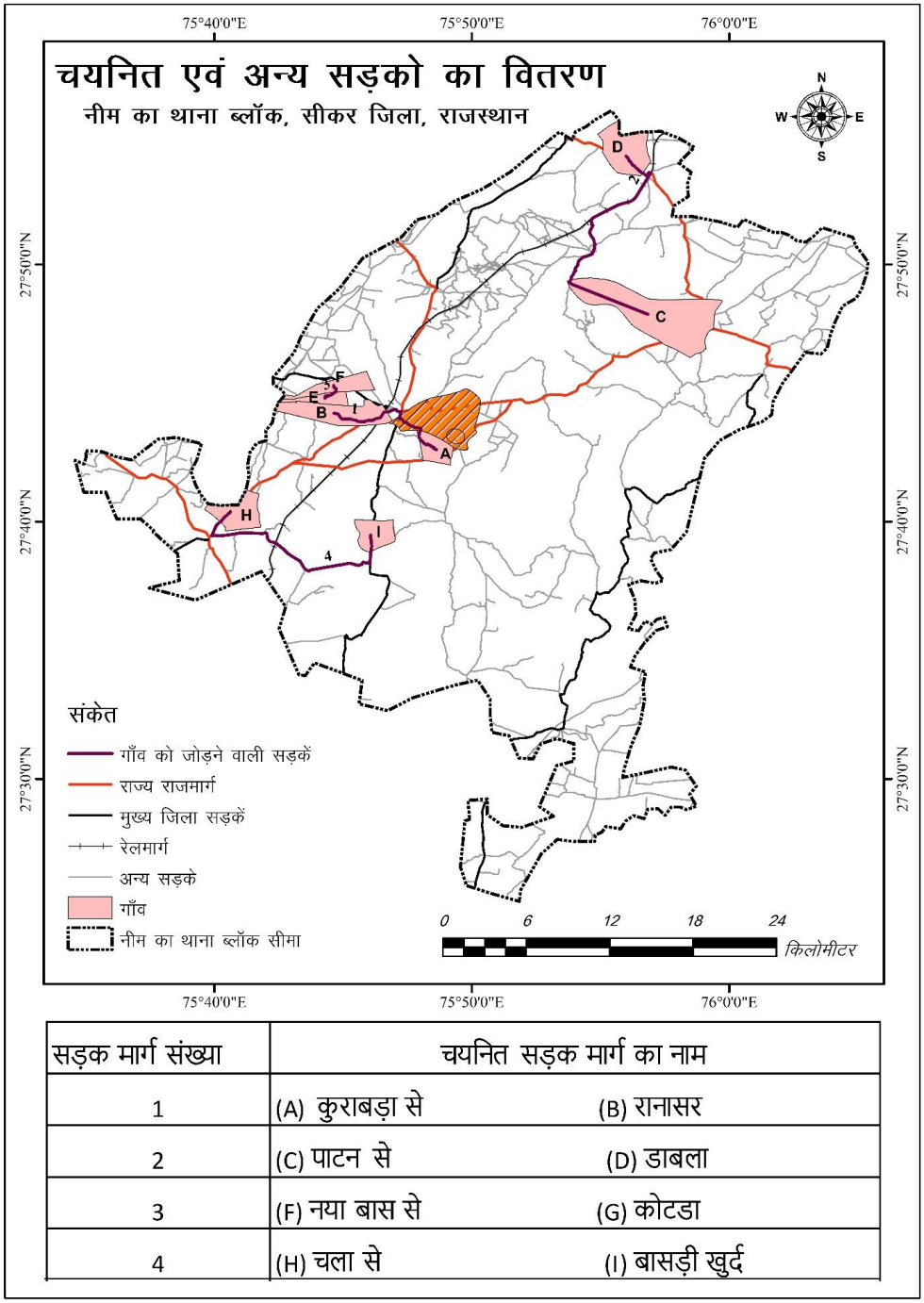

सड़क मार्ग संख्या	चयनित सड़क मार्ग का नाम	
1	(A) कुराबड़ा से	(B) रानासर
2	(C) पाटन से	(D) डाबला
3	(F) नया बास से	(G) कोटडा
4	(H) चला से	(I) बासड़ी खुर्द

शोध उद्देश्य एवं विधि तत्रं

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख उद्देश्य प्रधानमंन्त्री ग्राम सड़क योजना का अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन व मूल्यांकन करना है। इस हेतु शोधकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र से 4 सड़क मार्गो (पी. एम. जी. एस. वाई.) का जनसंखया समूह के आधार पर गांवो का चयन स्तरित विधी द्वारा

किया गया है। चयनित प्रत्येक गांव से 15–15 उत्तरदाताओं का चयन करते हुए कुल 90 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची व समूह चर्चा के माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया। व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो को सारणी व आरेख के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षो का मूल्याकन किया गया है।

तालिका संख्या 1 : नीमकाथाना ब्लॉक में पीएमजीएसवाई का विस्तार

वित्तीय वर्ष	नई संपर्कता		उन्नयन	
	सड़को की संख्या	सड़क की लंबाई (कि. मी. में)	सड़को की संख्या	सड़क की लंबाई (कि. मी. में)
2000-2001	02	07.000	03	09.000
2001-2002	05	16.200	00	0.000
2002-2003	03	15.500	00	0.000
2003-2004	03	06.850	00	0.000
2004-2005	00	00.000	00	0.000
2005-2006	03	09.400	00	0.000
2006-2007	01	02.000	00	0.000
2007-2008	00	00.000	02	24.480
2008-2009	00	00.000	01	11.000
2009-2010	00	00.000	00	00.000
2010-2011	00	00.000	00	00.000
2011-2012	04	07.950	00	00.000
2012-2013	03	04.500	00	00.000
2013-2014	07	11.730	00	00.000
2014-2015	00	00.000	00	00.000
2015-2016	00	00.000	00	00.000
2016-2017	04	06.000	00	00.000
2017-2018	00	00.000	01	08.300
2018-2019	00	00.000	00	00.000
2019-2020	00	00.000	00	00.000
2020-2021	00	00.000	02	10.000

2021-2022	00	00.000	00	00.000
2022-2023	00	00.000	00	00.000
2023-2024	00	00.000	00	00.000
कुल	35	87.130	09	62.780

स्त्रोत : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली, http://ommms.nic.in/Home/Citizenpage/#

तालिका संख्या 2 : चयनित सड़क मार्गो का विवरण

सड़क मार्ग संख्या		1	2	3	4
चयनित सड़क मार्ग का नाम		कुरबड़ा से रानासर	पाटन से डाबला	नया बास से कोटड़ा	चला से बासड़ी खुर्द
गाँव का नाम		कुरबड़ा	पाटन	नया बास	चला
जनसंख्या	2001	1495	5346	2105	3547
	2011	2428	7004	3185	5984
गाँव का नाम		रानासर	डाबला	कोटड़ा	बासड़ी खुर्द
जनसंख्या	2001	1095	3895	1103	1095
	2011	1791	6378	1653	1596
सड़क निर्माण वर्ष		2000–01	2007–08	2008–09	2020–21
सड़क मार्ग की लम्बाई (किलोमीटर में)		08	13.230	11	05

स्त्रोत : जनगणना, 2001, 2011 सार्वजनिक निमार्ण विभाग, लिला सीकर

समाजिक विकास पर प्रभाव

अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक विकास के अंतर्गत शैक्षिक, प्रसासनिक एवं स्वास्थ्य सेवाओंके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है– सामाजिक विकास के विभिन्न पक्षों पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनर का प्रभाव :–

आरेख संखया : 1

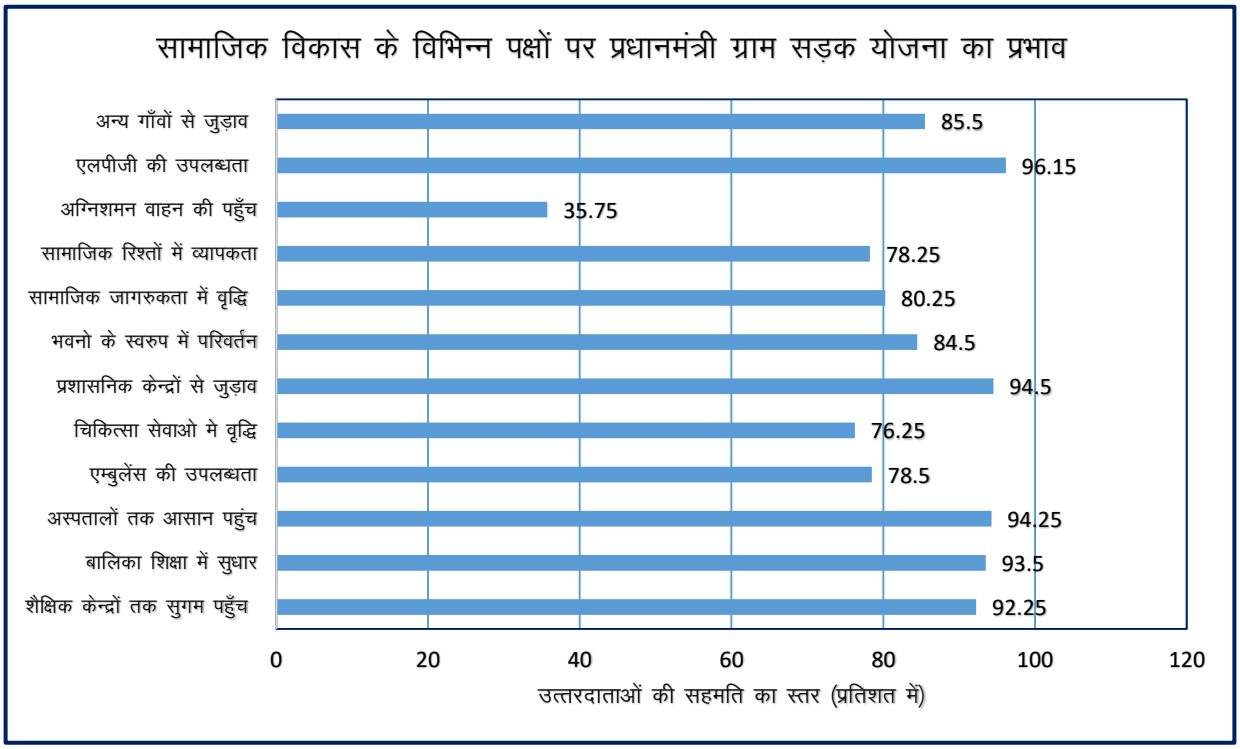

स्त्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों से शोधार्थी द्वारा निर्मित, 2025

1. शिक्षा पर पभाव :–

शैक्षिक केन्द्रों तक सुगम पहुँच – क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे इस क्षेत्र में आवागमन की दृष्टि से असहजता महसूस करते थें या फिर बीच सत्र में विधालय छोड़देते थे। मगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क मार्ग विकास के बाद परिवहन सुविधा उपलब्ध होने से बालक–बालिकाएँ विधालय जाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव आसानी से पहुंचते हैं। साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा भी बाल वाहिनी की सुविधा गाँव/ढाणी तक उपलब्ध हो पायी है। 92.25 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत है कि प्रधानमंन्त्री ग्राम सड़क योजना पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की शैक्षिक केन्द्रों तक पहुँच में सुगमता हुई है।

बालिका शिक्षा में सुधार– अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंन्त्री ग्राम सड़क योजना से बालिका शिक्षा में सुधार हुआ है। 93.50 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत है कि बालिकाएं गांव में उपलब्ध विधालय स्तर तक की पढाई कर पाती थी क्योकि गांव में आवागमन सुविधा के अभाव में बालिका विधालय/महाविधालय तक पहुंच पाने में असमर्थ रहती थी। परंतु प्रधानमंन्त्री ग्राम सड़क योजना से सड़क

निमार्ण होने के कारण अब सड़क मार्ग से जुड़े गांवो में सार्वजनिक यातायात के साधनों की सुविधा उपलब्ध होने लगी है। इसके साथ–साथ आज गांव की बालिकाएं साइकिल, दुपहिया वाहन, आदि से महाविधालय तक आसानी से व नियमित रुप से पहुंच पा रही है। इससे बालिकाओं को उच्च शिक्षा भी प्राप्त हो रही है।

2. स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव

अस्पतालों तक आसान पहुंचः प्रधानमंन्त्री ग्राम सड़क योजना से पूर्व आवागमन के साधनो के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल तक पहुंच पाना मुश्किल होता था मगर प्रधानमंन्त्री ग्राम सड़क योजना से सड़को के निर्माण उपरांत परिवहन साधनों की सुलभता से किसी भी स्तर के अस्पताल तक पहुंच पाना बहुत आसान हो गया है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 94.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सड़क निर्माण से अस्पतालो तक कम समय में आसानी से पहुंच कर सेवाओं का लाभ ले रहे है।

एम्बुलेंस की उपलब्धताः क्षेत्र सर्वेक्षण नीमकाथना से 78.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सें सड़क निर्माण से एम्बुलेंस सुविधा की पहुच में आसानी हुई और दुर्घटना एवं प्रसव के समय अस्पताल पहुंचने में लगने वाले समय में काफी कमी आयी है जिससे समय रहते उचित उपचार मिल पाता है।

चिकित्सा सेवाओ मे वृद्धिः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पूर्व सड़को के अभाव के कारण गांवो मे समय पर टीकाकरण समय पर नही हुआ करता था लेकिन अब 76.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ये कार्य अब समय पर होता है।

3. प्रशासनिक केन्द्रों से जुड़ाव

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सें सड़क निर्माण से इन गांवो तक प्रसासनिक सुविधा सुलभता सुनिश्चित हुई है। समूह चर्चा व 94.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि सड़कों के अभाव में इन क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे न के बराबर होते थें परंतु सड़क निर्माण से स्थानीय ग्रामीणें की प्रशासनिक केन्द्रों तक सुविधाजनक पहुँच में वृद्धि हुई है जिससे प्रशासन से जुड़ाव के साथ–साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी समय–समय पर मिलती है।

4. भवनो के स्वरुप में परिवर्तन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सें सड़क निर्माण के बाद ग्रामीणें की पहुँच शहरों तक सुगमता के साथ अधिक हो गई है। जिाका प्रभाव भवन निमार्ण प्रतिरुप व सामग्री पर स्पष्ट देखने को मिलता है। 84.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि आजकल गांवों में भी परिवहन सेवाओं के विस्तार से भवन निर्माण सामग्री उचित दर व कम लागत पर आसानी से मिल पा रही है।

5. सामाजिक जागरुकता में वृद्धि

अध्ययन क्षेत्र नीमकाथना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सें सड़क निर्माण से लोगो का आपसी सम्पर्क बढ़ा है जिससे सामाजिक जागरुकता में वृद्धि हुई है। 80.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि आजकल गांवों में सामाजिक जागरुकता में वृद्धि हुई है। जैसे बालिका शिक्षा व महिलाओं की सहभागिता, परिवार नियोजन में सुधार तथा अंधविश्वास रुढ़िवादिता, दहेज प्रथा, बाल–विवाह, मृत्यु भोज आदी में कमी देखने को मिली है।

6. सामाजिक रिश्तों में व्यापकता

अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सें सड़क निर्माण से गांव वालों का सामाजिक संपर्क दूर–दराज के गांवों से भी होने लगा है। 78.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि आजकल गांवों में सामाजिक रिष्तों में व्यापकता देखने को मिलती है। इसलिए सड़क निर्माण से ग्रामिणों की सामाजिक व सामुदायिक कार्यक्रमों में भागिदारी में वृद्धि हुई है।

7. अग्निशमन वाहन की पहुँच

ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी घटनाएं घरों/झोपड़ीं या फिर खेत–खलिहानों में होने से आग बुझाने हेतु शहर/नगर निगम/नगर पालिका से अग्निशमन वाहन की पहुंच पक्की सड़क अभाव में बिल्कुल भी नही थी। 35. 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि सड़क बनने के बाद अग्निशमन वाहन की पहुंच केवल उन्ही गांवो में है जो शहर/तहसील मुख्यालय/नगरपालिका से कम दूरी पर स्थित है तथा जहां सड़क सुविधा हैं।

8. एलपीजी की उपलब्धता

अध्ययन क्षेत्र नीमकाथाना में 96.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सड़क निर्माण के बाद विभिन्न गैस एजेंसियों से नियमित गैस वाहन घर व गांवों तक पहुंच पा रहे है तथा साथ ही आवश्यकता होने पर स्वयं के वाहन, सार्वजनिक परिवहन द्धारा भी ग्रामीणों की पहुंच गैस एजेंसी तक स़ंभव हो पायी हैं।

9. अन्य गाँवों से जुड़ाव

अध्ययन क्षेत्र नीमकाथना में 85.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सड़क निर्माण के बाद लोगों का अन्य गाँवो से जुड़ाव में वृद्धि हुई है। एक गाँव से दूसरे गाँव में आना जाना आसान हुआ है सिससे लोगों का जुड़ाव बढ़ा है।

आर्थिक विकास पर प्रभाव

अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले का नीमकाथाना ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर किया गया हैं–

आरेख संख्या–2

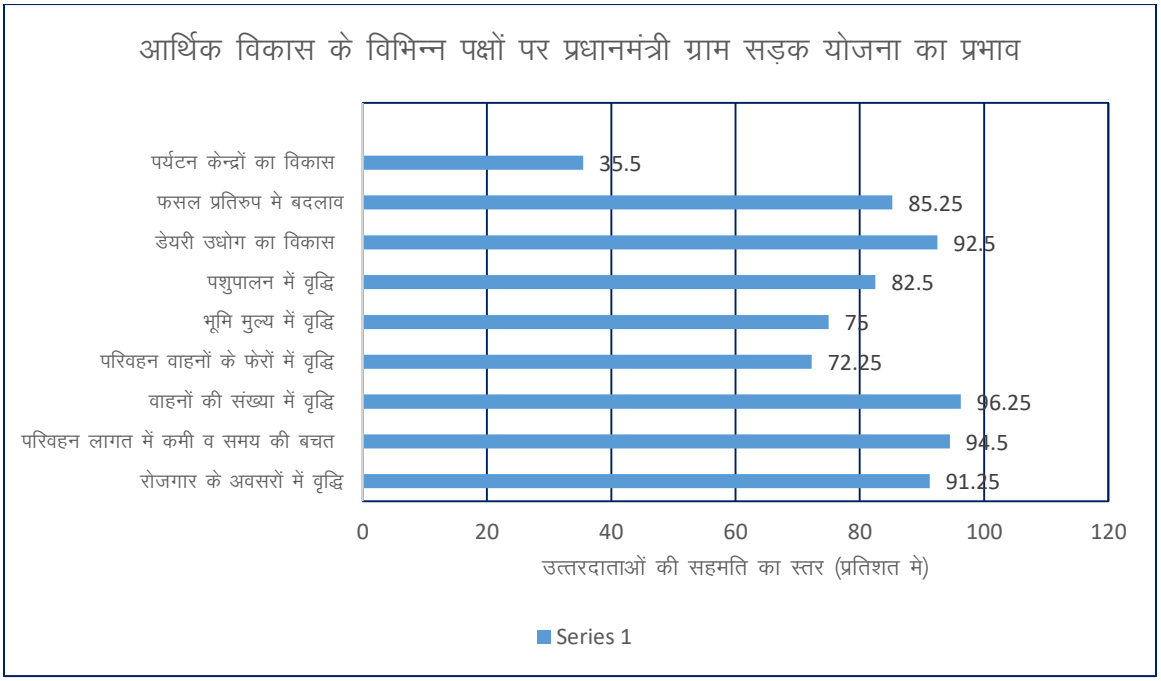

1. **रोजगार के अवसरों में वृद्धिः** उपरोक्त आरेख संख्या–2 के अनुसार 91.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क मार्ग से जुड़ने से रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ। सड़क निर्माण से श्रमिक वर्ग, कर्मचारी वर्ग व बेरोजगार वर्ग की गांव व शहर दोनों में ही आसानी से उपलब्धता हो पायी है। समूह चर्चा में ग्राम वासियों ने बताया कि सड़क मार्ग बनने से पहले बहुत सारी दैनिक आवश्यकता के सामानों की पूर्ति हेतु निकटवर्ती शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था जबकि सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अनेक विकल्प मिले जिनमे फल–सब्जियों, आटा–चक्की दुकान, किराण स्टोर, हेयर ड्रेसर, टेलर, वाहन सर्विस सेन्टर, हार्डवेयर–फर्नीचर उघोग, ई–मित्र व मेडिकल की दुकान आदि प्रमुख है।
2. **परिवहन लागत में कमी व समय की बचतः** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामिण जनसंख्या को एक–दूसरे क्षेत्रों से जोड़ने का काम किया है क्योंकि इसके माध्यम से गावों व शहरों के बीच की दुरी कमहो गयी हैं। अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पूर्व इन गांवों में सरकारी बस व निजी आवागमन के साधनों का अभाव था। लेकिन अध्ययन के 94.50 प्रतिशत उत्तरदाताओ नं माना है कि सड़क निर्माण के बाद संपर्क सुविधा बढ़ने से परिवहन लागत में कमी आई हैं।
3. **वाहनों की संख्या में वृद्धि** : अध्ययन क्षेत्र में सड़क निर्माण से पूर्व मे वाहनों की संखा कम थी सड़क निर्माण के बाद सर्वाधिक वृद्धि दुपहिया वाहनों की हुई, इसके साथ ही चौपहिया वाहनों की संख्या भी बढ़ी 96.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव की कनेक्टिीविटी होने से वाहनों की संखया में भारी इजाफा हुआ है।

4. **परिवहन वाहनों के फेरों में वृद्धि** : अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण से परिवहन वाहनों के फेरों में वृद्धि हुई है इस बात की 72.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुष्टी की है।
5. **भूमि मुल्य में वृद्धि** : अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण से योजना का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्य में वृद्धि के रुप में देखने को मिलता है। इससे गांवो में न केवल सड़क मार्ग के नजदीक बल्कि दूरी पर स्थित कृषि व आवासीय भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस दौरान भूमि उपयोग में भी परिवर्तन हुआ है। जहा पहले या तो बंजर भूमि थी या कृर्षि की जाति थी वहां पर अब अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी विकसित हो रही है। इस बात की 75.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुष्टी की है।
6. **पशुपालन में वृद्धि** : अध्ययन क्षेत्र में 82.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण से कृर्षि के साथ–साथ पशुपालन व्यवसाय में भी वृद्धि हुई है जिसमें मुख्यतः भेड़, बकरी, गाय, भैस, ऊँट तथा मुर्गीपालन है।
7. **डेयरी उधोग का विकास** : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सडक निर्माण से दूध संकलन वाहनों की पहुँच घरों तक हो गयी हैं जिससे ग्रामीणों को दूग्ध एवं दुग्ध से सम्बन्धित उत्पादों जैसे–मावा, पनीर आदि का उचित मुल्य मिलने से उनकी आय में वृद्धि हुई हैं। यह 92.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है।
8. **फसल प्रतिरुप मे बदलाव** : क्षेत्र सर्वेक्षण से 85.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद कृर्षि में उन्नत बीजों, उर्वरकों की उपलब्धता, कृर्षि उपजों के उचित मूल्यों की प्राप्ति, कृर्षि में आधुनिक मशीनीकरण के उपयोग में वृद्धि आदि सम्मिलित कारकों के कारण फसल प्रतिरुप में बदलाव हुआ है जिससे क्षेत्र में व्यवसायिक कृषि मुख्यतः प्याज, ग्वारपाठा (एलोवेरा) की खेती में वृद्धि हुई है।
9. **पर्यटन केन्द्रों का विकास** : अध्ययन क्षेत्र में सड़क विकास से पर्यटन का सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाकलाप के साथ–साथ आथिक गतिविधियों में भी योगदान बढा है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 35.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद स्थानिय पर्यटन का विकास हुआ है।
10. **जीवन स्तर में सुधार** : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना **में** सड़क विकास से ग्रामीण आबादी के सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में चहुँमुखी बदलाव व सुधार होने तथा परिवहन सेवाअसें में विस्तार से संसाधनों के उपभोग में वृद्धि के साथ जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जिससे ग्रामिण आधुनिक सुविधाओ का उपयोग कर रहे है।

निष्कर्श

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण भारत का स्वरुप बदल रहा है। जिसके माध्म से न केवल ग्रामीण आबादी को आवागमन व माल वहन हेतु सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है बल्कि इसके सहारे सामाजिक– आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सुगम सड़क परिवहन व सड़क संयोजन की अभिगम्यता में वृद्धि होने से चहुँमुखी आर्थिक विकास के साथ–साथ

लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण सड़क विकास से कृषि भूमि फसल प्रतिरुप में बदलाव स्वरुप व्यावसायिक कृषि जैसे एलोवेरा, ककडी, तरबुज, खरबुजा एवं सब्जियाँ आदि के स्वरुप में बडा परिर्वतन हुआ है। ग्रामिण सड़के विभिन्न दूर–दराज गाँवों के मध्य सम्पर्क के साथै–साथ कस्बों, शहरों/नगरों और औधोगिक केन्द्रों को उनके पृष्ठ प्रदेशों से भी जोड़ती है जो सामाजि–आर्थिक उन्नति का परिचायक है।

अध्ययन क्षेत्र में सड़क सम्बद्धता से धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजनो एवं पर्यटन केन्द्रों के विकास से स्थानिय लोगों के साथ–साथ सड़क से जुड़े अन्य गाँवो के लोगो को भी रोजगार प्राप्त हुआ है। इस योजना द्वारा सड़क विकास से कृषको. गैर कृषि मजदूरों तथा अकुशल श्रमिको को भी अन्य गांवों. कस्बों. नगरों एवं औधोगिक क्षेत्रो से जुड़ाव होने से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए है जिससे उन्हें काम और मजदूरी के अनेक अवसर मिलने से उनकी वार्षिक आय में भी वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागिदारी में वृद्वि हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है की अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सामाजिक– आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों में सकारातमक योगदान है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- कौशिक, देवेश, 2012 परिवहन भूगोल, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
- यादव, राम गणेश, 2014.भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ. 18–27
- बंसल, सुरेश चन्द्र, 2019. पर्यटन भूगोल एवं यात्रा प्रबन्धन, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, पृ. 42–47
- जिला जनगणना पुस्तिका–जिला सीकर 2011– भारतीय जनगणना विभाग
- जिला सांख्यिकी पुस्तिका–जिला सीकर 2023–24 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
- Itewar. M & Anand. U. 2019. An Impact of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) on Non-Agricultural Labourers: an Empirical Study in Sagar District. International Journal of Humanities and Social Scince Invention, 8(2): 43-50
- www.pmgsy.nic.in